CONTENTS

INDEX

TITLE	Page(s)
NEP-2020 और स्त्री शिक्षा - **डॉक्टर गुरमीत कौर**	02
माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्रावधान - **प्रतिभा तिवारी**	08
ROLE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE FOR ACADEMIC ACHIEVEMENT FOR CHILDREN IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS - **Rakesh Kumar Keshari**	14
Police & Criminal Justice System in India - **Saba Hashmi**	22
Swayam Portal: Empowering Education through Online Learning - **Mr. Manoj Kumar**	39
प्लास्टिक से पर्यावरण को खतरा, क्या हैं विकल्प - **पुष्पेंद्र कुमार ठाकुर**	51

DVS International Journal of Multi-Disciplinary Research ISSN NO 2454-7522
Vol: 8, ISSUE: 4, No: 32 April – June, 2023

माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्रावधान

प्रतिभा तिवारी
शोधार्थी

प्रस्तावना-

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सभी को रहने खाने के साथ-साथ शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का संतुलित विकास होता है, और व्यक्तियों के संतुलित विकास से देश का विकास होता है। शिक्षा के द्वारा मानव अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास को बढ़ावा देने की मूलभूत आवश्यकता है। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण भारत की सतत् प्रगति आर्थिक विकास की कुंजी है। भारत सबसे युवा जनसंख्या वाला देश है और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा।

सतत् विकास लक्ष्य या एजेंडा 2030 में 17 लक्ष्य निर्धारित किये गये है जिसमें सतत् विकास लक्ष्य 4 शिक्षा पर केन्द्रित है, जिसका शीर्षक "समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना।" 2030 तक यह सुनिश्चित करे कि सभी लड़के और लड़कियों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण वाली प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करे, जिससे प्रभावी शिक्षण परिणाम प्राप्त हो सके। 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जो किसी देश से पीछे न रहे। जहाँ पर ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जो किसी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से सम्बन्ध रखने वाले विद्यार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध हो सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परम्परा और सांस्कृतिक मूल्यों को संजोये रखेगी। यह नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं को विकास पर विशेष बल देती है इस नीति में बुनियादी क्षमताओं तार्किक एवं समस्या समाधान के साथ-साथ नैतिक सामाजिक और भावनात्मक गुणों का विकास करना है। इस नीति में सभी विद्यार्थियों के लिए चाहे उनका स्थान कहीं भी हो उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जायेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 -

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जो कि 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। वर्ष 1968 तथा 1986 के बाद यह भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इस नीति के तहत केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में देश की जीडीपी का 6% शिक्षा में निवेश करने का लक्ष्य रखा गया। इस नीति के अध्यक्ष पूर्व इसरो प्रमुख कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन जी है। इस नीति के माध्यम से भारत सरकार ने शिक्षा के कई क्षेत्रों में उन्नति के लिए नए विचारों का समावेश किया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिन्दुः-

1. इस नीति के अनुसार बच्चों को 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे बच्चों को स्कूल में कम से कम 15 वर्ष की शिक्षा अवधि मिलेगी।
2. इस नीति के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में समानता को बढ़ावा दिया गया है। समान शिक्षा की पहली योजना बनाकर, अलग-अलग जातियों और क्षेत्रों के छात्रों के लिए एक समान शिक्षा मॉडल तैयार किया गया है।
3. इस नीति के द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था को संवैधानिक बनाना, सभी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना।
4. विद्यार्थियों के समुचित विकास के लिए पाठ्य सहगाभी क्रियाए तथा अन्य क्रियाए करना।
5. इस नीति में शिक्षा के क्षेत्र में नए-नए अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना।
6. इस शिक्षा नीति में डिजिटल शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को बदलना और विद्यार्थियों को डिजिटल जीवन की तैयारी करना।

माध्यमिक शिक्षा का संक्षिप्त परिचय-

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीयों के हृदय में देश की शीघ्र प्रगति के लिए असीम उत्साह था, देश के नेताओं ने देश के चहुमुखी विकास के लिए बड़े-बड़े स्वप्न संजोये हुए थे, जो कि शिक्षा के द्वारा ही पूरा होना था। जिसके लिए इस क्षेत्र में ध्यान दिया गया, उच्च शिक्षा के विकास के लिए विश्वविद्यालय आयोग की संस्तुति आ चुकी थी। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत सरकार को सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा का गठन की आवश्यकता है, भारत सरकार ने बोर्ड के सुझाव को स्वीकार किया तथा 23 सितम्बर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ0 लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया,

आयोग ने शिक्षा सम्बन्धी बहुत सुझाव दिये। इसके पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में 10$2 को अपनाया गया। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उस समय के मांग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम शिक्षण विधि अध्यापक प्रशिक्षण, मूल्यांकन आदि में सुधार किया गया।

माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्रावधान-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारत सरकार द्वारा लाई गई एक नीति है, जो भारत के शैक्षणिक संस्थानों के विकास और उसके गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बनायी गयी है। यह नीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानको के आधार पर तैयार की गयी है, इसका मुख्य ध्येय भारत के शिक्षा संस्थानों को आधुनिकीकृत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिपूर्ण बनाना है।

1. शैक्षणिक ढ़ांचाः-

इस नीति में शिक्षा के शैक्षणिक ढ़ांचे में परिवर्तन किया गया है, इसमें 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 को शामिल किया गया है। जिसके तहत क्रमशः फाउंडेशनल स्टेज (दो भागों में अर्थात् आंगनवाड़ी/प्री-स्कूल के 3 साल + प्राथमिक स्कूल में कक्षा 1-2 में 2 साल, 3 से 8 वर्ष के बच्चों सहित), प्रिपेटरी स्टेज (कक्षा 3-5, 8 से 11 वर्ष के बच्चों सहित), और सेकेंडरी स्टेज (कक्षा 9 से 12 दो फेज में, यानी पहले फेज में 9 और 10 और दूसरे में 11 और 12, 14 से 18 वर्ष के बच्चों सहित) शामिल होगी।

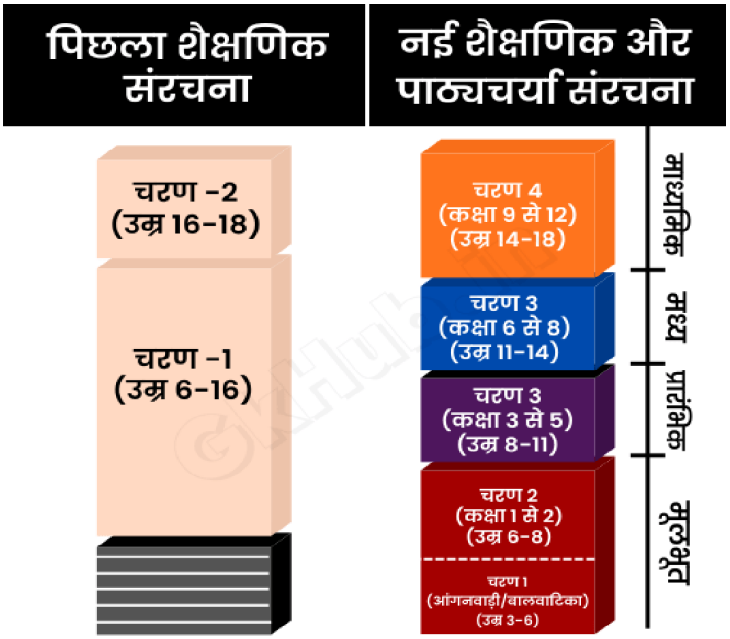

2. भाषाः-

इस नीति के तहत बच्चों को उनकी मूल भाषा में शिक्षा दी जायेगी ताकि वे बेहतर ढ़ंग से सीख सके और माध्यमिक शिक्षा के बच्चों के लिए मूल भाषा के साथ-साथ वे रसियन, फ्रेंच, जापानी, पुर्तगाली, जर्मन आदि अन्य विदेशी भाषाओं को सीख सकते है ताकि छात्र विश्व-संस्कृति के बारे में जाने तथा घूमने-फिरने में सहजता मिल सकें।

3. डिजिटल शिक्षाः-

इस नीति में माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने में डिजिटल शिक्षा प्रदान की जायेगी। इससे छात्र आनलाइन शिक्षण डिजिटल पुस्तकालय और नये-नये अनुसंधान, पत्र-पत्रिका आदि को पढ़ सकेगे और जिस विषय में अधिक रूचि होगी उसके बारे में अधिक जानकारी ले सकेगे।

4. नई शिक्षण पद्धतिः-

इस शिक्षा नीति में शिक्षण पद्धतियों में कई बदलाव किए गए है इसमें बालक को रटा करके पढ़ाया नहीं जायेगा बल्कि उन्हें स्वयं करके सीखने, समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि आदि का उपयोग करके शिक्षा प्रदान की जायेगी जिससे बच्चों को आसानी से विषय वस्तु समझ आ सके।

5. बोर्ड परीक्षाः-

इस नीति में माध्यमिक शिक्षा के बोर्ड परीक्षा को पहले से अधिक लचीला बनाया गया है जिससे परीक्षा का डर खत्म हो सके। इसमें वर्णनात्मक तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन होगा यह परीक्षा वर्ष में दो बार होगी।

6. पाठ्यक्रमः-

इस नीति के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों समाहित किया गया है। जिसमें भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी आदि। माध्यमिक शिक्षा में किसी विषय वर्ग को चुनने की आवश्यकता नहीं है, विद्यार्थी की जो इच्छा हो जिस विषय में उसका मन अधिक लगता है उस विषय का चुनाव कर सकता है। जैसे भूगोल के साथ भौतिक विज्ञान और लेखाशास्त्र।

7. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमः-

इस शिक्षा नीति में शिक्षकों के लिए अलग-अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम और संसाधन उपलब्ध होगें, उन्हें नवीनतम शिक्षण प्रणाली तकनीकी के उपयोग छात्र केन्द्रित शिक्षा स्वयं अध्ययन और समस्या हल आधारित शिक्षा जैसे अनुभव प्रदान किये जायेगें। शिक्षकों की क्षमताओं को विस्तार करने के लिए नवीनतम शिक्षण विधियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा और शिक्षकों को अपने विषय के क्षेत्र में नवाचार करने के लिए प्रेरित किया जायेगा।

8. प्रयोगशाला का विकासः-

इस नीति के तहत अब स्कूलों में अधिक प्रयोगशाला का विकास होगा ताकि विद्यार्थी अधिक संवेदनशील विषयों को प्रयोगशाला के माध्यम से सीख सकेगे। प्रयोगशाला के द्वारा रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कम्प्यूटर जैसे अनेक विषयों को समझने में मद्द मिलती है। स्कूलों में प्रयोगशालाओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

9. मूल्यांकन प्रणालीः-

इस नीति में माध्यमिक शिक्षा में मूल्यांकन प्रणाली को लोचदार बनाया गया है अब इसमें मूल्यांकन केवल ज्ञान का ही नही होगा बल्कि ज्ञान के साथ-साथ उनके क्रियाकलाप सहपाठी के साथ व्यवहार पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी मूल्यांकन होगा। मूल्यांकनकर्ता शिक्षक मित्र तथा उसके अभिभावक तीनों होगें। मूल्यांकन प्रणाली में छात्र के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए अंको के साथ-साथ अन्य कार्यों और शैलियों का भी मूल्यांकन किया जायेगा।

10. रिपोर्ट कार्डः-

रिपोर्ट कार्ड छात्र की प्रगति का सूचक होता है अब रिपोर्ट कार्ड में छात्र के परीक्षा में प्राप्त अंकों के साथ-साथ छात्र की कक्षा में उपस्थिति, छात्र द्वारा की गई अतिरिक्त गतिविधि का विवरण जैसे-खेल, कला, साहित्य आदि का विवरण दर्शाया जायेगा।

निष्कर्ष-

माध्यमिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण चरण है जो छात्रों को उनके शैक्षणिक और व्यक्तिगत विकास के लिए तैयार करती है। इस अवधि में छात्रों को अधिकतर शैक्षणिक विषयों का ज्ञान होता है जो उन्हें आगामी शैक्षणिक और पेशेवर लक्ष्यों के लिए तैयार करती है। माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा के बीच में कड़ी कार्य करता है। उच्च शिक्षा में आगे क्या करना है इसका निर्धारण माध्यमिक शिक्षा से होता है किसी भी नीति की सफलता उसके क्रियान्वयन पर

निर्भर करती है यदि क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी। इस नीति का उद्देश्य अच्छे मनुष्यों का विकास करना होता है, जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हों, जिनमें करूणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पनाशक्ति, नैतिक मूल्य हैं। जोकि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित-समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें।

सुझाव-

1. माध्यमिक शिक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए नियमित अंतराल पर आवश्यकतानुसार शिक्षक भर्तियों को प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि अन्य छात्र भविष्य में इसके प्रति आकर्षित हो सकें और देश को बेहतर शिक्षक मिल सकें।
2. माध्यमिक शिक्षा में अवसरों की समानता पर बल दिया जाए इसके लिए इस स्तर पर अधिकाधिक छात्रवृत्ति प्रदान करने की व्यवस्था की जाए।
3. लड़कियों, जनुसूचित जातियों एंव जनजातियों में माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए।
4. माध्यमिक शिक्षा संस्थानों की समय-समय पर मॉनीटरिंग किये जाए ताकि उनमें शिक्षकों एवं छात्रों की उपस्थिति कार्यक्रमों के संचालन, गुणवत्ता आदि का पर्यवक्षेण करके उनकी गुणवत्ता, विश्वसनीयता की जांच की जा सके।
5. माध्यमिक शिक्षा में कम्प्यूटर शिक्षा को अनिवार्य विषय कर देना चाहिए जिससे छात्र कम्प्यूटर से आनलाइन कक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी से शिक्षा को ग्रहण कर सके और भविष्य में कम्प्यूटर के क्षेत्र में रोजगार भी प्राप्त कर सकेगें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020
- शर्मा, उषा, (2022): राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 रचनात्मक सुधारों की ओर, नई दिल्ली।
- कुमार, डॉ0 ज्ञानेन्द्र और पारोक डॉ मोनिका,: राष्ट्र शिक्षा नीति-2022 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा-प्रावधान और चुनौतियाँ।
- www.ncte.gov.in, Retrieved on 20/03/2023 at 07:00 pm.
- www.hi.vikaspedia.in, Retrieved on 21/03/2023at 09:00 pm.
- www.ncert.nic.in, Retrieved on 22/03/2023 at 10:00 pm.